

प्रेषक,

राकेश शर्मा,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा,
हल्द्वानी, नैनीताल।

शिक्षा अनुभाग-7 (उच्च शिक्षा) देहरादून दिनांक 25 अक्टूबर, 2012
विषय:- वित्तीय वर्ष 2012-2013 में राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय रुद्रपुर
में आवासीय भवन निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-423/xxiv(7)46(2)/2011 दिनांक 17.03.2011 एवं आपके पत्र संख्या डिग्री विकास/5425/2012-13 दिनांक 14.08.2012 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 में राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय रुद्रपुर के आवासीय भवन निर्माण हेतु शासनादेश संख्या 907/XXIV(7)/2006 दिनांक 11.12.2006 द्वारा अनुमोदित लागत रु. 187.50 लाख के विरुद्ध देय अवशेष धनराशि रु. 87.01 लाख के सापेक्ष रु. 50.00 लाख (रु0 पचास लाख मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- स्वीकृत धनराशि को उपरोक्त कार्य के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य में व्यय नहीं किया जायेगा तथा अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति की प्रत्याशा में कोई अन्य व्यय नहीं किया जायेगा एवं समय-समय पर निर्गत वित्तीय एवं मित्तव्यता सम्बन्धी नियमों एवं दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का आहरण निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा करने के उपरान्त सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त किया जायेगा।

3- स्वीकृत धनराशि के उपयोग के सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत समस्त शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा निर्माण कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को अवगत कराया जायेगा। निर्माण कार्य के लिये अवमुक्त की गई धनराशि का उपभोग तथा कार्य पूर्ण किया जाना शीघ्रता से इसी वित्तीय वर्ष में करने के लिये प्राचार्य द्वारा समुचित पर्यवेक्षण किया जायेगा तथा निर्माण इकाई द्वारा विलम्ब करने की दशा में शासन द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। विलम्ब की दशा में आगणन पुनरीक्षण पर विचार नहीं किया जायेगा।

4- निदेशक उच्च शिक्षा कार्यदाई संस्था को धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व कार्यदाई संस्था से एक सप्ताह में अवमुक्त की जाने वाली धनराशि के विरुद्ध एकेडिमिक रिक्वायरमेंट के अनुरूप समय सारणी अनुसार कार्य पूर्ण करने की लिखित सहमति प्राप्त कर लेंगे। यदि लिखित समयावधि के अन्तर्गत कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है तो, एक माह का ग्रेस पीरियड देते हुये कार्यदाई संस्था से 5 प्रतिशत आर्थिक जुर्माना वसूला जायेगा। तीन माह से अधिक विलम्ब होने पर कार्यदाई संस्था को काली सूची में सम्मिलित करने हेतु कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

5- तृतीय पक्ष गुणवत्ता (Third party quality) सुपरविजन तथा अनुश्रवण की व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाय, परन्तु निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें पूर्ण की जानी होंगी। इसका व्यय कार्यदायी संस्था को देय सेन्टेज चार्ज (Centage) से किया जायेगा।

6- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 के आय-व्यय की अनुदान सं० 11 के आयोजनागत पक्ष के अधीन लेखा शीर्षक-4202-शिक्षा खेल कूद तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-01-सामान्य शिक्षा-203-विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा-आयोजनागत-03-कतिपय राजकीय महाविद्यालयों के निर्माणाधीन भवनों को पूर्ण किया जाना-24-बृहत्त निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

7- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 95 (p)/xxvii (3)/2012-13 दिनांक 09 अक्टूबर, 2012 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राकेश शर्मा)
प्रमुख सचिव

सं० 1942(1) xxiv(7)/2012-46(2)/08 तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2-आयुक्त कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
- 3-जिलाधिकारी उधमसिंहनगर।
- 4-कोषाधिकारी हल्द्वानी-नैनीताल।
- 5-प्ररियोजना प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम, हल्द्वानी।
- 6-प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय रुद्रपुर।
- 7-निदेशक एन०आई०सी० उत्तराखण्ड।
- 8-बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन सचिवालय देहरादून।
- 9-वित्त अनु०-3/नियोजन प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड शासन।
- 10-गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(श्याम सिंह)
अनु सचिव